

21 वीं सदी में उत्तर प्रदेश विधान सभा व सरकार में अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की भागीदारी

अभय राज सिंह

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

Email: ars1688@gmail.com

सारांश

उत्तर प्रदेश में जाति सम्बन्धी जनगणना 1931 के बाद 2011 में संपन्न हुई लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया गया। 1931 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत में पिछड़े वर्गों की आबादी 52 प्रतिशत थी। जबकि उत्तर प्रदेश में इस वर्ग का प्रतिशत 41.70 था। बाद के विभिन्न आयोगों व समितियों के आंकलन के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अलग-अलग समय पर भिन्न रही है। लेकिन इन आयोगों द्वारा जारी तथ्यों के आधार पर कालानुक्रम में उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 54.50 प्रतिशत है। 50 प्रतिशत से अधिक आबादी होने पर भी 21वीं सदी में 2002 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न चार विधान सभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 से 33 प्रतिशत विधायक चुने गये। इस वर्ग का प्रतिशत पूर्व के चुनावों की तुलना में 1989 के बाद से धीरे-धीरे बढ़ा है। लेकिन यह प्रतिनिधित्व कभी भी 1967 के चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के रिकार्ड को न तोड़ सका है और न ही उसके करीब पहुँच सका है। इस समयकाल में चार विधान सभा चुनाव में कुल 5 सरकारों का गठन हुआ। इन सरकारों में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 30 से 38 प्रतिशत के मध्य स्थिर है।

Reference to this paper
should be made as follows:

Received: 14.09.2020

Approved: 30.09.2020

अभय राज सिंह

21 वीं सदी में उत्तर प्रदेश
विधान सभा व सरकार में
अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी

*RJPP 2020,
Vol. XVIII, No. II,
pp.240-246
Article No. 30*

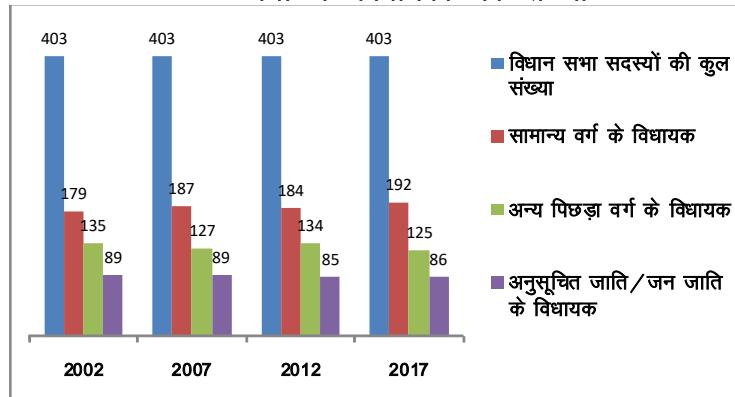
Online available at :
[https://
anubooks.com/
?page_id=6391](https://anubooks.com/?page_id=6391)

21 वीं सदी में उत्तर प्रदेश विधान सभा व सरकार में अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की भागीदारी

अमय राज सिंह

रेखाचित्र (ग्राफ)-1

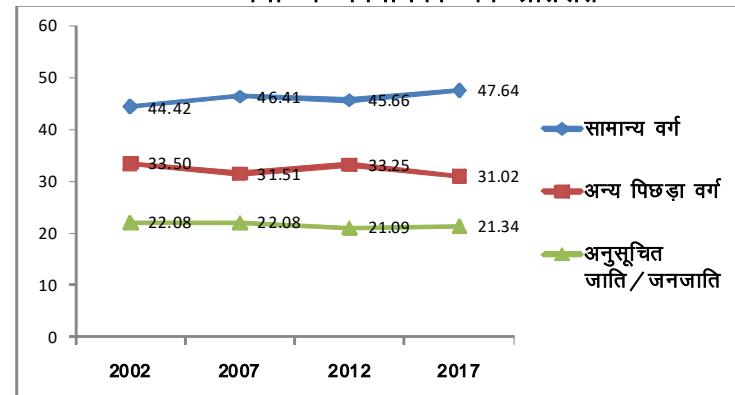
उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधान सभा चुनावों (2002 से 2017 तक) में विभिन्न वर्गों के विधायकों की संख्या



Source: शोधार्थी द्वारा निर्मित

रेखाचित्र (ग्राफ)-2

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधान सभा चुनावों (2002 से 2017 तक) में विभिन्न वर्गों के विधायकों का प्रतिशत



Source: शोधार्थी द्वारा निर्मित

उत्तर प्रदेश सरकार में अन्य पिछ़ड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व-

वर्ष 2002 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल चार विधान सभा चुनाव सम्पन्न हुए। लेकिन इन चार विधान सभा चुनाव में कुल 5 सरकारों का गठन हुआ। 2002 के विधान सभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के गठबन्धन की सरकार बनी। इस सरकार का नेतृत्व सुश्री मायावती ने किया। इस सरकार में कुल 79 सदस्यों की मंत्रिपरिषद गठित की गयी। इस मंत्रिपरिषद में सामान्य वर्ग के 54.43 प्रतिशत मंत्री, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग से 29.11 प्रतिशत मंत्री

व अनुसूचित जाति से 16.46 प्रतिशत मंत्री बनाये गये। यह सरकार गठबंधन की सरकार थी। जो विभिन्न राजनीतिक करणों से डेढ़ वर्ष ही चल सकी। इसके बाद अगस्त 2003 में समाजवादी पार्टी की श्री मुलायम सिंह के नेतृत्व में सरकार गठित हुई। इस मंत्रिपरिषद में कुल 98 सदस्यों को शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद है। इस मंत्रिपरिषद का वर्गीय विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि 54.08 प्रतिशत मंत्री सामान्य वर्ग से, 38.78 प्रतिशत मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से व 7.14 प्रतिशत मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग के बनाये गये।

तालिका-3

उत्तर प्रदेश सरकार में वर्ष 2002 से 2017 तक विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व

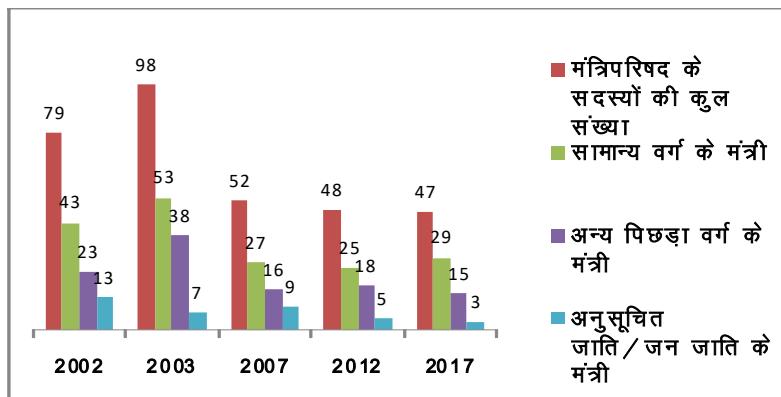
वर्ष	मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या	सामान्य वर्ग के मंत्री संख्या		अन्य पिछड़ा वर्ग के मंत्री		अनुसूचित जाति/जन जाति के मंत्री	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2002	79	43	54.43	23	29.11	13	16.46
2003	98	53	54.08	38	38.78	7	7.14
2007	52	27	51.92	16	30.77	9	17.31
2012	48	25	52.09	18	37.49	5	10.42
2017	47	29	61.71	15	31.91	3	6.38

Source: शोधार्थी द्वारा फील्ड वर्क पर आधारित।

वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 206 सीटें जीतकर सुश्री मायावती के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी। इस मंत्रिपरिषद में कुल 52 सदस्यों को मंत्री बनाया गया। इसमें सामान्य वर्ग से 51.92 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग से 30.77 प्रतिशत व अनुसूचित जाति से 17.31 प्रतिशत मंत्री बनाये गये।

रेखाचित्र (ग्राफ)-3

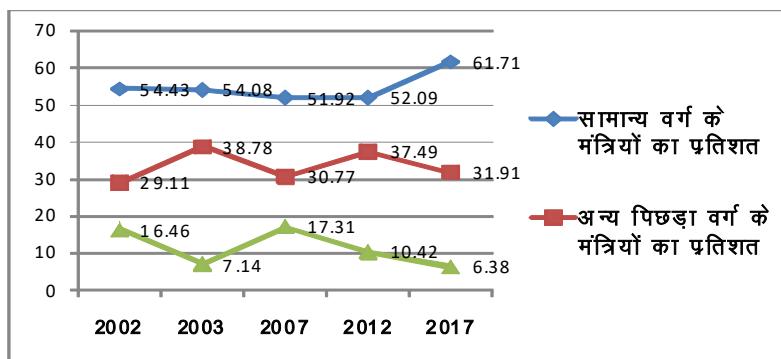
उत्तर प्रदेश सरकार में वर्ष 2002 से 2017 तक विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व



Source: शोधार्थी द्वारा निर्मित

रेखाचित्र (ग्राफ)-4

उत्तर प्रदेश सरकार में वर्ष 2002 से 2017 तक विभिन्न वर्गों की सहभागिता का प्रतिशत



Source: शोधार्थी द्वारा निर्मित

सोलहवीं विधान सभा के चुनाव 2012 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें प्राप्त हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार का नेतृत्व श्री अखिलेश यादव ने किया। इस सरकार में कुल 48 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। श्री अखिलेश यादव की मंत्रिपरिषद में 52.09 प्रतिशत सदस्य सामान्य वर्ग के सम्मिलित किये गये। अन्य पिछड़ा वर्ग के 37.49 प्रतिशत सदस्यों को मंत्रिपरिषद में स्थान प्राप्त हुआ। वहीं अनुसूचित जाति के 10.42 प्रतिशत सदस्यों मंत्री बनाये गये।

वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें प्राप्त हुईं जो कि कुल संख्या का लगभग दो तिहाई है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री आदित्यनाथ “योगी” के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया। इस मंत्रिपरिषद में 47 सदस्य हैं। जिसमें 61.71 प्रतिशत सामान्य वर्ग के, 31.91 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के व 6.38 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों को शामिल किया गया।

समग्र रूप से देखा जाये तो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश सरकार में 1984 के बाद 2017 में सर्वाधिक है। सामान्य वर्ग की सहभागिता में कमी दलितों व पिछड़ों के राजनीतिक उभार के बाद आयी। इस प्रक्रिया में दलितों व पिछड़ों के बड़े नेताओं का भी प्रभाव कहा जा सकता है।

पिछले कुछ चुनावों में लगभग तीन दशक से उत्तर प्रदेश विधान सभा में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 25 से 30 प्रतिशत के लगभग रहा है। सामान्य रूप से एक चौथाई सीटों पर प्रतिनिधित्व को किसी भी रूप में कम नहीं कहा जा सकता है लेकिन जो समूह जनसंख्या के आधे से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता हो और राजनीति रूप से महत्वपूर्ण पर हाशिये का समाज हो, उस समूह के प्रतिनिधित्व प्रतिशत का अधिक होना उस वर्ग के उन्नयन व सामाजिक व राजनीतिक समानता के लिये आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. Census 1931, *United Provinces of Agra and Awadh*, Part 2, Provincial and Imperial Tables, 1933. Adopted by Rise of the Plebians? The Changing Face of Indian Legislative Assemblies. New Delhi: Routledge, pp. 32.
2. Government of India. *Report of The Backward Class Commission*. Vol.1. 1955.
3. Government of India. *Report of The Backward Class Commission*. First Part. Volumes 1 & 2. 1980, pp.11
4. समाजिक न्याय समिति उत्तर प्रदेश सरकार 2001.
5. *Handbook on Social Justice Welfare Statistics*. Government of India Ministry of Social Justice and Empowerment.2018-19, pp. 237-238.
6. Performance of political parties E.C.I. State Election. 2002,2007,2012,2017 to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh .
7. Jaffrelot, Christophe and Sanjay Kumar. 2009. *Rise of the Plebians? The Changing Face of Indian Legislative Assemblies*. New Delhi: Routledge.
8. Kothari, Rajni (1970). *Politics in India*. New Delhi: Orient Blackswan.
9. Kothari, Rajni (2010). *Caste in Indian Politics*. New Delhi: Orient Blackswan.
- 10 सदस्य परिचय: उत्तर प्रदेश की 14वीं, 15वीं, 16वीं व 17वीं विधान सभा.